उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–07(02/46)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को जी न्यूज, उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित ''एक शाम, देश के नाम'' कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि शहीदों का सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान देश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड के शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश पर, देश के सैनिकों पर गर्व होता है। राज्य सरकार ने सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सरकार की कोशिश है कि राज्य के सैनिकों, अर्द्धसैनिकों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(02/45)

दिनांक 08 फरवरी, 2019 को उत्तराखण्ड के हरिद्वार व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के सीमावर्ती गांव में जहरीली शराब के सेवन के कारण कतिपय ग्रामीणों के मृत्यु को दुखद घटना के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

आबकारी मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बताया कि जनपद हरिद्वार के रूड़की क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक, जनपद प्रवर्तन के आबकारी निरीक्षक तथा अधीनस्थ स्टॉफ कुल 13 आबकारी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

- प्रवर्तन कार्य से सम्बन्धित समस्त उच्चाधिकारियों अपर आयुक्त से लेकर सहायक आयुक्त तक व जिला आबकारी अधिकारी को प्रवर्तन कार्य में लापरवाही बरतने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
- समस्त जिलाधिकारी को प्रभावी प्रवर्तन कार्य करने हेतु आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग व राजस्व विभाग की टीम गठित कर अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
- जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जहरीली शराब काण्ड के सम्बन्ध में एक मजिस्ट्रेट इनक्वायरी के आदेश निर्गत किये गये हैं। जांच अधिकारी एक पक्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- जनपद हरिद्वार में घटना की पुनरावृत्ति रोके जाने हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल, उपायुक्त हरिद्वार परिक्षेत्र, जनपदीय प्रवर्तन दल हरिद्वार व मण्डलीय प्रवर्तन दल हरिद्वार की टीम गठित कर अग्रिम आदेशों तक रूड़की में ही कैंप कर अवैध मदिरा रोकने के निर्देश दिये गये हैं।
- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मण्डल के मण्डल आयुक्त से सम्पर्क कर जनपद सहारानपुर व हरिद्वार के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर सीमावर्ती संदिग्ध ग्रामों में दबिश का आयोजन कराया गया है।
- जहरीली शराब के प्रकरण में प्रथम दृष्टया मैथाईल एल्कोहॉल के होने के सम्भावना के दृष्टिगत राज्य में स्थित समस्त मेथाईल एल्कोहॉल से सम्बन्धित अनुज्ञापनों की सघन जांच करायी जा रही है।
- आबकारी आयुक्त दिनांक 10.02.2019 को प्रभावित क्षेत्रों में जायेंगे तथा की जा रही कार्यवाही का मौके पर पर्यवेक्षण करेंगे।
- शासन द्वारा समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी की समन्वय समिति गठित कर अवैध मदिरा की तस्करी रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
- दिनांक 08.02.2019 व 09.02.2019 को राज्य में अवैध शराब के विरूद्ध किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार हैः–
    1. आई0डी0–28 अवैध शराब का बनाना
    2. ओ0एल0–21 शराब पकड़ने के प्रकरण
    3. कुल अभियोग–49
    4. पकड़ी गयी कच्ची शराब–965 बी0एल0
    5. पकड़ी गयी देशी शराब–65.7 बी0एल0
    6. पकड़ी गयी विदेशी शराब–36.1 बी0एल0
    7. कुल पकड़ी गयी शराब–1066.91 बी0एल0
    8. नष्ट किया गया लहन–27400 कि0ग्रा0
- उपरोक्त में जनपद हरिद्वार में की गयी प्रवर्तन कार्यवाही का विवरणः–
    1. कुल अभियोग 02
    2. पकड़ी गयी कच्ची शराब–30 बी0एल0
    3. लहन–800 कि0ग्रा0

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(02/44)

- **ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरीः मुख्यमंत्री**
- **ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह भी होगी प्रशस्तः मुख्यमंत्री**
- **जानकी झूलापुल का निर्माण समयबद्धता से किया जाएः मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मुनि की रेती ऋषिकेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन जानकी सेतु, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना एवं नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।

सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुनि की रेती ऋषिकेश में बनाए जा रहे जानकी झूलापुल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जानकी झूलापुल का निर्माण समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुम्भ से पूर्व इस पुल का निर्माण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से 2021 में होने वाले कुंभ मेले में बहुत सहायता मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस झूलापुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जानकी सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। इस झूलापुल की चौड़ाई भी बढ़ाई गई है। इस पुल का निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष में पूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण से लोगों की वर्षों पुरानी मांग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का जो संकल्प लिया है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग के बीच रेल लाईन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि चारधाम सम्पर्क के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य में पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों का आवागमन बढ़ने के साथ ही उन्हें सुविधा भी होगी। ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह भी प्रशस्त होगी। इस योजना के पूर्ण होने से उत्तराखण्ड के पर्यटन में बहुत बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ऋषिकेश इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं एस0टी0पी0 योजना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सीवेज समस्याओं से निजात मिलेगी। इस अवसर पर बताया गया कि लक्कड़ घाट पर 26 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट के कार्यों की प्रगति 25 है, जिसके कार्य माह अगस्त 2019 में पूर्ण हो जाएंगे। राइजिंग मेन का कार्य भी प्रगति पर है, 1.5 किमी में से 600 मीटर राइजिंग मेन बिछाई जा चुकी है। 13.5 किमी लंबी ग्रेविटी सीवर में से 200 मीटर लाइन बिछाई जा चुकी है। सीवेज पंपिंग स्टेशन का कार्य माह अगस्त 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता ममगांई, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली एवं सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(02/43)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बसंत पंचमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होने सभी की खुशहाली व प्रगति की कामना करते हुए आशा व्यक्त की है कि बसंत ऋतु उत्तराखण्ड वासियों के जीवन में नई उमंग और उत्साह का संचार करेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बसंत पंचमी का यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है। बसंत पंचमी का पर्व प्राकृतिक सौन्दर्य एवं नई ऊर्जा के संचार का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए संकल्प लेने की अपील की है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(02/42)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया

- **1100 करोड़ रूपये से बनेगा सौंग बांध।**
- **सौंग बांध के निकट के क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा।**
- **बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौंधना गांव में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार दूरगामी सोच के साथ काम कर रही है। बढ़ते जनसंख्या दबाव में शहरों में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन उपायों पर काम किया जा रहा है। 1100 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली सौंग बांध परियोजना पूरे देहरादून जिले को चौबीस घण्टे पानी उपलब्ध करवाएगी। इससे 100 करोड़ रूपये का बिजली का खर्च बचेगा। इस साढ़े चार किलोमीटर लम्बे व 128 मीटर ऊंचे बांध के आस–पास के क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा। इस परियोजना को 350 दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। सौंग परियोजना द्वारा रायपुर क्षेत्र तक ग्रेविटी बेस्ट पानी की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हम दीर्घकालीन व सस्टेनेबल समाधान की ओर बढ़ रहे है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सौंग बांध क्षेत्र को पर्यटन वैली के रूप में विकसित किया जायेगा। इस क्षेत्र में 20–25 पनचक्कियों का क्लस्टर भी बनाया जायेगा। इस बांध परियोजना की भारत सरकार के स्तर पर भी सराहना की गई है कि यह देश के लिए एक मॉडल परियोजना हैं। सौंग बांध निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिसके तहत बरसात के दिनो को छोड़कर इसमें निरन्तर काम चलेगा। यह बांध व झील पर्यटन आकर्षण का नया केन्द्र बनेगा। स्थानीय लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने सचिव सिंचाई एवं सचिव वित्त को निर्देश दिये कि सौंग बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। इस अवसर पर प्रमुख अभियन्ता सिंचाई ए.के. दिनकर द्वारा सौंग बांध परियोजना की तैयारियों को लेकर चल रहे टेस्टिंग कार्य व सर्वे कार्यो की जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर देहरादून के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार, सचिव सिंचाई डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए मुरूगेशन व जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल श्रीमती सोनिका आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(02/41)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भगवानपुर तहसील के गांवों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु होने की घटना का संज्ञान लेते हुए घटना में मृतकों के आश्रितों को 02–02 लाख रूपये तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50–50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकारियों को घटना की जानकारी मिलते ही दे दी थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जहरीली शराब घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई इस पर एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि वास्तविकता का पता चले। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर काईवाई की जायेगी। ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में आबकारी व पुलिस के 17 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इस मामले की जांच के लिए एडीएम हरिद्वार की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब बिक्री से सम्बन्धित कोई भी मामला सामने आता है तो सम्बन्धित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर कारवाई की जायेगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 09 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(02/40)

पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिया जाए–मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र

- **योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता के चिन्हीकरण में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए।**
- **मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाए जिससे लाभार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके । मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के बीपीएल व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश के 441264 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन, 157246 को विधवा पेंशन, 75389 को दिव्यांग पेंशन 24481 को किसान पेंशन व 3910 को परित्यक्त पेंशन से लाभान्वित किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों के वृद्धजनों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी वर्गों की निराश्रित बीपीएल विधवाओं को भी 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी वर्गों के बीपीएल श्रेणी वाले परिवारों के दिव्यांगजनों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत तीलू रौतेली दिव्यांग पेंशन, बौने व्यक्तियों को पेंशन योजना में 1 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन तथा जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को 700 रूपये प्रतिमाह दिव्यांग भत्ता भी दिया जा रहा है। किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को प्रतिमाह 1 हजार रूपये की दर से किसान पेंशन दी जा रही है। किसान पेंशन योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएं जो बीपीएल हो, को 01 हजार रूपये प्रतिमाह तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को 1200 रूपये प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने बताया कि अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पहले राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से छात्र–छात्राओं के बैंक खातों में ऑनलाईन दी जा रही थी। अब छात्रवृत्ति का संचालन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अब छात्रवृत्ति कोषागार के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में ऑनलाईन दी जा रही है। 10 दिन के अन्दर बैकलॉग का वर्ष 2017–18 की छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा। इसके लिए ब्रिज साफ्टवेयर बनाया गया है।

बैठक में बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 16.90 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग हैं। अल्पसंख्यक कल्याण के तहत प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 14162 छात्रों को 4 करोड़ 50 लाख रूपये की छात्रवृत्ति दी गई। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है को 11 वीं कक्षा से पीएचडी स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 1675 छात्र–छात्राओं को 1 करोड़ 21 लाख की छात्रवृत्ति दी गई है।

बैठक में निदेशक समाज कल्याण श्री विनोद गिरी गोस्वामी, निदेशक अल्प संख्यक कल्याण श्री धीरेन्द्र सिंह दताल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग